



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ 1940 (श10)
(सं0 पटना 83) पटना, वृहस्पतिवार 24 जनवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

10 जनवरी 2019

एस0ओ0 21 दिनांक 24 जनवरी 2019—जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-328मु0/विधि, दिनांक 06.10.2018 के अनुसरण में औरंगाबाद जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप औरंगाबाद जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण), अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री रविन्द्र कुमार, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-580/1968 है, को नियुक्ति के तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही प्रसंगाधीन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त की जायेगी।

3. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु उन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।

4. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक माह विषयांकित वादों (निष्पादीत व लम्बित) से सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष में जनवरी तथा जुलाई माह में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित अधिनियम से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

6. संबंधित विशेष लोक अभियोजक यदि लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील/ किसी अधिनियम के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक/सरकार द्वारा प्रायोजित किसी परियोजना के पद पर कार्यरत है, तो उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। इन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।

(सं०-सी०/ए०एस०-3-28/2007/207/जे०,)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव कुमार,

सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 83-571+25-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>